श्री राम नरेश यादव : मैं प्रश्न कर रहा हूं। जो धान की सीडलिंग होती है, जिससे धान की रोपाई की जाती है, वह भी सूख गई है इसकी प्रदेश के किसी हिस्से में आवश्यकता ही नहीं रही। किसान तो उससे महरूम हो गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो सूखा न हुआ है, प्रदेश की सरकार की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकते हैं कि खरीफ की कितनी फसल के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है और जो मोटे अनाज होते थे, उनकी क्षति का कितना अनुमान लगाया गया है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश की सरकार से इस संबंध में कोई रिपोर्ट मंगवायेंगे। दूसरी बात यह है इसके साथ-साथ, क्योंकि किसान का सारा खाने का सामान घर से बाहर चला गया, उसने बोआई कर दी, उसके पास कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। अब वह रबी की बोआई कैसे करेगा ? इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे से जो यह सारी तबाही हुई है अगली आने वाली रबी की फसल की बोआई के लिए केन्द्र सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है, प्रदेश सरकार को क्या निर्देश देने जा रही है ? जिस किसी तरह से भी हो, जिन सारी चीजों की कमी होगी, बीज की कमी होगी, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : सभापति जी, जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि धान की रोपाई नहीं हो सकती। अब देखने और सुनने में बड़ा अंतर आ जाता है। मैं तो स्वयं देख कर आया हूं।

श्री राम नरेश यादव: मैं अभी चार दिनों में गया था देवरिया गया था, गोरखपुर, आजमगढ़ और लखनऊ गया था। इन सारी जगहों पर घूम कर आया हूं। मैंने देखा है और अपने जिले में भी देखा है **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : मैं स्वयं देख कर आया हूं। धान लगता हुआ मैंने देखा है, लोगों को धान लगाते हुए देखा है। लेकिन जहां नहीं है वहां हमने उत्तर प्रदेश सरकार को बीज चाहिए तो बीज दो, खाद चाहिए तो खाद दो और जो हमसे सहायता हो सकती है– और हमने पर्णरूपेण आदेश दिये हुए हैं कि जो आपको साधन चाहिए उनको जुटाना आपका परम कर्तव्य भी है और उसको निभाना भी आपका धर्म है, आप करिए, जो हमसे सहायता चाहते हैं हम देंगे।

Procedure adopted by Railway Claims Tribunal or paying compensation to kith and kin of accident victims

*85. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the procedure adoped by Railway Claims Tribunal in deciding the compensation claims by the kith and kin of a victim in any Railway accident;

(b) what is the minimum time taken by the Tribunal in deciding a claim;

(c) whether all the claims have been cleared by the Tribunal which came before it during the last three years;

(d) if not, the details thereof; and

(e) by when all these claims are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The procedure is prescribed in the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989.

(b) Three months.

(c) No, Sir.

(d) Of the 1559 cases filed before the Tribunal since its inception in November 1989, 1069 cases have already been adjudicated.

(e) No accurate estimate can be given

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, रेल एक्सीडेंटस की वजह से मृतकों की संख्या में पिछले तीन वर्षों में लगातार जो वृद्धि हो रही है वह बहुत दुर्भाग्यजनक है । अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 1,559 प्रकरण उन्हें मिले और निपटारा केवल 1,069 का हो पाया । कई बार यह बताया गया है कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पूरे मेंबर्स की नियुक्ति नहीं हुई है इसकी वजह से सारे प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाया, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने मेंबर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के होने चाहिये ? अभी कितने मेंबर बने हुये हैं, कौन कौन मेंबर किन किन तिथियों को बने और उनका कितना टेन्योर होता है ? जो प्रकरण 490 अभी बचे हैं जिनका निपटारा अभी तक नहीं किया गया है उसका क्या कारण है और चूंकि यह रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी है उन प्रकरणों को निपटाना तो उन मेंबर्स के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, the Railway Claims Tribunal is constituted with a Chairman, and the Chairman is a retired Judge of a High Court. There are two Members in every bench one is Judicial Member and the other is Technical Member. The Judicial Member is taken from the State Government Judicial Service or the national legal service or from the Bar. So far as the Technical is concerned, he is railwayman who has got adequate knowledge in commercial field and claims. We have got about 18 such benches. All have been constituted. There is no .....

MR. CHAIRMAN: No vacancy?

SHRI MALLIKARJUN: Nothing as such. All have been fully constituted.

So far as the cases are concerned, within these twenty months, out of 1,559 applicaions filed, 1049 have been cleared and 490 are still pending.

SHRI SURESH PACHOURI: It is 1,069 not 1,049.

SHRI MALLIKARJUN: No, 1,049.

SHRI SURESH PACHOURI: It has been given in your answer.

SHRI MALLIKARJUN: Okay. It makes no difference. It is 1,069.

Sir, what has been left over is 490. Here all the cases have been cleared with speed except in Bhopal. In Bhopal, out of 214 applications filed, only 24 cases have been cleared.

MR. CHAIRMAN: Why have you chosen Bhopal for this purpose?

SHRI MALLIKARJUN: I am coming to that point.

SHRI N. K. P. SALVE: You are particularly concerned about Bhopal only.

SHRI MALLIKARJUN: Now 190 are left over. In this what has happened is that on 26th February, 1989 there was a train accident between Howbagh and Jabalpur on the narrow gauge. Unfortunately, Sir, the victims have to file applications, and other procedures will have to be gone through.

In this case quite a number of tribal women and children are involved. The Claims Tribunal, to speed up the process and finalise the cases, even had special sittings at Jabalpur from 14 to 16 in November, 1990 and again from 8 to 12 in July, 1991. Unfortunately, these people are not coming forward. However, we have to see that these cases are finalised.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, यह सदन पूरा सहमत होगा कि किसी भी परिवार में जब रेल दुर्घटना की वजह से मृत्यु होती है, तो वह उस परिवार के लिये सब से बड़ा सदमा होता है । तात्कालिक खर्च के लिये

केवल पांच हजार रुपये की राशि सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को दी जाती है, जोकि बहुत कम है। और उसके बाद जो क्लेम्स किये जाते हैं, उनका भी निपटारा करने में काफी ज्यादा समय लगता है।

क्या उसकी कोई समय सीमा निर्धारित की जायगी कि इतने समय के अन्दर उन केसेज का निपटारा हो जायेगा?

दूसरे मंत्री जी ने खुद स्वीकारा है कि लगभग 10 प्रतिशत केसेज का निपटारा भोपाल क्षेत्र में हुआ है। भोपाल के साथ यह ज्यादती क्यों हो रही है? क्या इस ज्यादती के लिये जो जिम्मेदार ट्रिब्यूनल के मेम्बर हैं उन पर आप कार्यवाही करने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा ?

तीसरे, ट्रिब्यूनल के गठन से पूर्व यदि कोई रेल एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या मृतक के परिवार जन क्लेम कर सकते हैं ? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? इसके साथ ही मृतक के परिवार जनों के लिये व्यस्क के लिये कितनी राशि का प्रावधान है, क्लेम लेने के लिये और अव्यस्क के लिये कितना है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा ?

SHRI MALLIKARJUN: There is no fault on the part of the Members of the Claims Tribunal. It is a question initiative. Somebody has to take initiative and bring the cases before the tribunal. There are laid-down procedures and the Tribunal will have to go through the laid-down procedures. Every attempt is made by the Claims Tribunal to dispose of the cases as early as possible unless and until there are some legal lacunae.

So far as the question of compensation in death cases is concerned, it has been increased from Rs. 1/- lakh to Rs. 2/- lakh. In the case of injuries, I have got a big list of compensation. It is from Rs. 16,000/- to Rs. 1,80,000/-.

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री जी यह कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के मेम्बर्स का दोष नहीं है। भोपाल में 214 प्रकरण है और केवल 24 का निपटारा हुआ है। और उसके लिये आप उन ट्रिब्यूनल के मेम्बर्स का बचाव कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि जो इसको चलाने वाले है जो क्लेमेंट हैं, वह नहीं आ रहे हैं।

श्री सुरेश पचौरी : : मान्यवर केसेज कब तक निपटायेंगे इसका पूरा उत्तर नहीं मिला है।

श्री सभापति : वह जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे।

SHRI MALLIKARJUN: Keeping in view the rate at which the cases are being disposed of by the Claims Tribunal, it will take about a year to complete the 490 cases. But it depends upon the claimants, particularly the Adivasis to come forward. I would appeal to the hon. Member to give some free legal aid to such people Such an arrangement exists in every State. This would be enable them to fulfil the minimum requirement of filling an application before the Tribunal.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: The compensation paid to the kith and kin of the victims of the railway accidents is very meagre as compared to the compensation paid to the kith and kin of the victims of air crashes, Higher compensation should be paid because loss of life is same, multilition of the body is same and sorrw of the family is same. If the Government are not in ia a position to increase the financial quantum of compensation, will they introduce an insurance scheme in the railways for the protection of the railway passengers?

SHRI MALLIKARJUN: I have already informed the august House that the compensation has been raised recently, in 1990 itself, from Rs. 1/- lakh to Rs.

2|- lokh. So. far as the question of insurance is concerned, at the moment we do not have any proposal before us.

MR. CHAIRMAN : He has given a suggestion. Will you consider it?

SHRI MALLIKARJUN : No, Sir.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: The ordeal of the people going to the Claims Tribunals is greater. The Railway Ministry has fixed a quantum of compensation in cases of deaths and injuries. So, what is the necessity for going to the Tribunals ? As soon as they produce the legal heir certificates from the competent authority, can't the Tribunal or the person concerned pay the amount immediately in order to avoid the ordeal 12.00 NOON of the people going to the Tribunals? Sir, going to the Tribunal causes a great hardship to the persons injured in the accidents because it is known that he is injured. So where is the question of proving the accident and other things ? The fatal accident has occured, the identity of the person who died is known then, where is the question of again going to the Tribunal and giving the evidence. This procedure should be simplified. Those who die in the accident, if their relatives get a legal death certificate and produce it before the Station Superintendent or anybody...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Loans from Sugar Development Fund

*82. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of FOOD be pleased to state, the details of scheme for granting loans to new sugar factories from the Sugar Development Fund?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): A sugar undertaking which has been operational for a minimum of seven crushing seasons including trial crushing season is eligible to avail Sugar Development Fund (SDF) loans for modernisation/rehabilitation. Each application for loan from SDF is considered on merit as per the provisions contained in the Sugar Development Fund Act, Rules and the general guidelines. No loan is given from SDF for setting up a new sugar factory.

Setting up of sugar factory in Gujarat

*86. SHRI CHHOTUBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Gujarat for change of the location for establishment of a new Sugar factory in the State; and

(b) by when the proposal is likely to be finalised ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) Ministry of Food has received five proposals for change of location in the State of Gujarat out of which four have been recommended by the Government of Gujarat, the details of the proposals are given in the Statement.

(b) Licensing Policy guidelines are presently being reviewed by the Government. As such, the above proposals for change of location would be considered after the aforesaid review.

Statement

S. No.	Name of the factory	From	To
1	2	3	4
1	M/s. Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd.	Rohid, Tal.—Hansot Distt.—Bharuch	Kosamba, Tal.—Mangro, Distt.— Bharuch.